

नाथुनी राम

बनाम

रघुपत राम और अन्य

23 फरवरी, 2007

[डॉ. अरिजीत पासायत और आर. वी. रवींद्रन, जे. जे.]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908; धारा 100:

मुकदमे की भूमि पर अधिकार की घोषणा और कब्जे की पुष्टि के लिए मुकदमा-मुकदमे की भूमि के हिस्से के संबंध में अपीलार्थी के दावे को स्वीकार करते हुए प्रथम अपीलीय न्यायालय-शेष भाग पर प्रतिवादियों के कब्जे की पुष्टि करने वाली भूमि-अपीलार्थी द्वारा पसंद की गई और प्रतिवादी द्वारा नहीं-उच्च न्यायालय द्वारा खारिज की गई प्रथम अपीलीय न्यायालय-क्षेत्र की शुद्धता द्वारा दी गई राहत को उलटते हुए: प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा दी गई राहत को उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिवादियों से किसी भी चुनौती के बिना भी उलट दिया गया था-इसलिए, अपील की अनुमति इस हद तक दी गई थी कि पहले अपीलीय न्यायालय-अभ्यास और प्रक्रिया-अपील द्वारा अपीलार्थी को पहले दी गई राहत की पुष्टि की गई थी।

अपीलार्थी ने स्वामित्व की घोषणा और वाद भूमि पर कब्जे की पुष्टि के लिए एक मुकदमा दायर किया। निचली अदालत ने मुकदमा खारिज कर दिया था। अपील पर, प्रथम अपीलीय न्यायालय ने 22 दशमलव भूमि के संबंध में अपीलार्थी के दावे की अनुमति दी और प्रतिवादियों को 14 दशमलव भूमि पर कब्जा करने की अनुमति दी। पीड़ित, अपीलार्थी ने सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के तहत एक अपील दायर की, जिसमें प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए विचार की शुद्धता पर सवाल उठाया गया। हालाँकि प्रतिवादियों ने पहली अपीलीय अदालत द्वारा व्यक्त किए गए विचार की शुद्धता पर सवाल नहीं उठाया था, फिर भी उच्च न्यायालय ने पहली

अपीलीय अदालत के एफ आदेश को दरकिनार कर दिया और निचली अदालत के फैसले की पुष्टि की। अपीलार्थी द्वारा दायर अपील को प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। अपीलार्थी एखनो प्रथम अपीलीय न्यायालय के फैसले से संतुष्ट नहीं था, उसने एक अपील दायर की, जिसे उच्च न्यायालय ने प्रथम अपीलीय न्यायालय के आदेश को दरकिनार करते हुए खारिज कर दिया। वास्तव में, जी प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को दी गई राहत को उलट दिया गया था। इसलिए वर्तमान अपील।

अपीलार्थी ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय द्वारा अपनाया गया मार्ग स्पष्ट रूप से कानून के विपरीत है और प्रतिवादियों द्वारा अपील के अभाव में उच्च न्यायालय के लिए विपरीत दृष्टिकोण रखने के लिए खुला नहीं है।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

उच्च न्यायालय के आदेश में बहुत भ्रम हैं; सबसे पहले अपील को खारिज कर दिया गया था, लेकिन पहले अपीलीय न्यायालय के आदेश को, जो अपीलार्थी के पक्ष में था, प्रतिवादियों से कोई चुनौती दिए बिना रद्द कर दिया गया था; दूसरा, अपीलार्थी की अपील में उस राहत को, जिस पर किसी ने सवाल नहीं उठाया था, रद्द नहीं किया जा सकता था; तीसरा, उच्च न्यायालय का बी अंतिम निष्कर्ष यह था कि अपील की अनुमति दी गई थी, जबकि वह अन्यथा थी। अतः, अपील को इस हद तक अनुमति दी जाती है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को दी गई राहत की पुष्टि हो जाती है। [पैरा 10 और 11]

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: 2007 की सिविल अपील सं. 910।

2002 के अपीलीय डिक्री संख्या 37 में रांची में झारखंड उच्च न्यायालय के निर्णय और अंतिम आदेश से।

अपीलार्थी की ओर से सुनील कुमार, अनीता कानूनगो और मृदुला रे भारद्वाज।

सैयद अली अहमद, सैयद तनवीर अहमद, एस. एस. बंदोपाध्याय, मोहम्मद।उत्तरदाताओं की ओर से शाह नवाज हसन, शबाना सैफी और मोहन पांडे।

न्यायालय का निर्णय डॉ. अरिजीत पासायत, जे. 1 द्वारा दिया गया था। छुट्टी दे दी गई।

2. इस अपील में चुनौती झारखंड उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए फैसले को दी गई है।वादी, जिसने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (संक्षेप में 'संहिता') की धारा 100 के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष दूसरी अपील दायर की थी, ने यह अपील दायर की है।

3. तथ्यात्मक पहलू का विस्तृत संदर्भ वास्तव में अनावश्यक है।

4. वादी ने स्वामित्व की घोषणा के साथ-साथ वाद भूमि पर कब्जे की पुष्टि के लिए मुकदमा दायर किया था।संपत्ति का विवरण प्लॉट संख्या 51 के रूप में दिया गया था, जो कि ग्राम जपला, धोरहारा, जिला पलामू के खाता संख्या 80 से संबंधित भूमि का 36 दशमलव था।इस मुकदमे को विद्वान मुन्सिफ डाल्टनगंज ने खारिज कर दिया था।

5. पहली अपीलीय अदालत में एक अपील दायर की गई थी।अपील में, विद्वान आठवें अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, पलामू ने अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी के दावे को 22 दशमलव भूमि के संबंध में स्वीकार किया जाना था और प्रतिवादी को 14 दशमलव से अधिक भूमि मिली थी। अपीलार्थी ने प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए विचार की शुद्धता पर सवाल उठाते हुए संहिता की धारा 100 के तहत अपील दायर की।

6. निम्नलिखित प्रश्न को दूसरी अपील में तैयार किया गया था जिसमें इसे कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न माना गया था।

"क्या निचली अपील अदालत ने भूखंड संख्या 51 की कुल 36 दशमलव भूमि में से 14 दशमलव पर वादी के दावे को अस्वीकार करने में कानूनी रूप से गलती की, जब 1342 फसली में प्राप्त रायती समझौते को नकार नहीं दिया गया था।"

7. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्रतिवादियों ने पहले अपीलीय न्यायालय के फैसले और डिक्री की शुद्धता सी पर सवाल नहीं उठाया था। इसके बाद भ्रम की शुरुआत होती है। यद्यपि प्रतिवादियों ने प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए दृष्टिकोण की शुद्धता पर सवाल नहीं उठाया था और यहां तक कि अपीलीय द्वारा दायर दूसरी अपील की सुनवाई के दौरान निष्कर्षों का समर्थन करने की कोशिश नहीं की थी, फिर भी उच्च न्यायालय ने प्रथम अपीलार्थी अदालत के आदेश को रद्द कर दिया और डी ने परिणामस्वरूप निचली अदालत के फैसले की पुष्टि की। मानो वह पर्याप्त नहीं था, अंतिम निष्कर्ष में उच्च न्यायालय ने नोट किया कि अपीलार्थी द्वारा दायर अपील की अनुमति दी गई थी। वास्तव में पहली अपीलीय अदालत द्वारा अपीलार्थी को दी गई राहत को उलट दिया गया था।

8. अपील के समर्थन में अपीलार्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय द्वारा अपनाया गया पाठ्यक्रम स्पष्ट रूप से कानून के विपरीत है। मान लीजिए कि 22 दशमलव भूमि के लिए अपीलार्थी की पात्रता के संबंध में पहली अपीलीय अदालत के दृष्टिकोण पर सवाल उठाने वाली कोई अपील नहीं थी। प्रतिवादियों द्वारा अपील के अभाव में उच्च न्यायालय के लिए एक विपरीत दृष्टिकोण लेने के लिए खुला नहीं था।

9. प्रत्यर्थियों के विद्वान वकील ने निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया कि उनके द्वारा पहली अपीलार्थी अदालत द्वारा दी गई राहत यानी 22 दशमलव भूमि तक कोई अपील दायर नहीं की गई थी। यह भी निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया गया कि उच्च न्यायालय के समक्ष उनके द्वारा इस आशय का कोई रुख नहीं अपनाया गया था कि अपीलार्थी को दी गई राहत कानूनी नहीं थी।

10. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, उच्च न्यायालय के आदेश में भ्रम की भरमार है; सबसे पहले अपील को खारिज कर दिया गया था, लेकिन पहली अपीलीय अदालत के आदेश को, जो अपीलकर्ता के पक्ष में था, प्रतिवादियों से किसी भी चुनौती के बिना रद्द कर दिया गया था; दूसरा, अपीलकर्ता की अपील में उस राहत को, जिस पर किसी ने सवाल नहीं उठाया था, रद्द नहीं किया जा

सकता था; तीसरा, उच्च न्यायालय का अंतिम निष्कर्ष यह था कि अपील की अनुमति तब दी गई थी जब वह अन्यथा।

11. ऊपर की स्थिति होने के कारण हम अपील को इस हद तक स्वीकार करते हैं कि पहली अपीलीय अदालत द्वारा अपीलार्थी को दी गई राहत की पुष्टि हो जाती है। उच्च न्यायालय का आदेश, जिसमें निर्देश दिया गया है कि अपीलीय न्यायालय के फैसले को उलट दिया जाए और निचली अदालत के फैसले को बहाल किया जाए, उस हद तक नहीं टिक सकता है।

12. अपील की अनुमति लागत के संबंध में किसी भी आदेश के बिना दी जाती है।

एस. के. एस.

अपील को अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।